स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्ला बोल

आधा वेतन मिलने पर काम बंद कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 अप्रैल। जिले के स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे लगभग 400 आउटसोर्स कर्मचारियों ने अल्प वेतन और सुविधाओं के अभाव में मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी जिला मुख्यालय पहुंचे और काम बंद कर हड़ताल करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित राशि का आधा वेतन ही दिया जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

वेतन विसंगति का गंभीर आरोप

हड़ताल का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी भानु धाकड़ और पूजा बुनकर ने बताया कि वे नवंबर 2025 से जिला अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं। नियमानुसार, आउटसोर्स कंपनी को प्रति कर्मचारी 475 रुपए प्रतिदिन (लगभग 14,250 रुपए प्रतिमाह) का भुगतान शासन से किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों के हाथों में मात्र 7,000 रुपए ही आ रहे हैं। कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि जब अन्य जिलों में पूरा भुगतान हो रहा है, तो शिवपुरी में उनके वेतन की कटौती क्यों की जा रही है।

सुविधाओं का अभाव और भेदभाव

ज्ञापन में कर्मचारियों ने उल्लेख किया कि वेतन कटौती के साथ-साथ उन्हें पीएफ (भविष्य निधि) और ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) जैसी अनिवार्य सरकारी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। भर्ती के शुरुआती चार महीनों में भी उन्हें इसी तरह आधा वेतन देकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

कंपनी को हो चुका है भुगतान

इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषेश्वर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित आउटसोर्स कंपनी को पूरा भुगतान समय पर कर दिया गया है। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा बिना पूर्व सूचना के काम बंद करने पर आपत्ति जताई, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि कंपनी प्रबंधन से चर्चा कर इस विसंगति को दूर किया जाएगा और जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों की हड़ताल से व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

आईटीआई के सामने खुली शराब दुकान पर आबकारी का शिकंजा, 10 दिन में हटाने के निर्देश

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 अप्रैल। शहर के महल सराय क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही एक शराब दुकान पर आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। आईटीआई परिसर के ठीक सामने खोली गई इस दुकान को लेकर विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है और 10 दिनों के भीतर दुकान को वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं।

नियमों की अनदेखी और जनविरोध : क्षेत्रवासियों की शिकायत के अनुसार, शराब दुकान के लिए निर्धारित परिक्षेत्र कहीं और था, लेकिन ठेकेदार ने मनमानी करते हुए इसे आईटीआई के सामने मुख्य मार्ग पर खोल दिया। इस

स्थान के समीप आईटीआई, बीटीआई और एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राओं का आवागमन होता है। स्थानीय निवासियों ने शैक्षणिक माहौल खराब होने की आशंका जताते हुए इसका कड़ा विरोध किया था।

आबकारी विभाग की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी वृत्त प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज ने स्थल निरीक्षण किया, जिसमें नियमों का उल्लंघन सही पाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि दी गई समय-सीमा में दुकान नहीं हटाई गई, तो ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस पहल से क्षेत्रवासियों और विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है।

पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति निराकरण विशेष शिविर 15 को : जिले के नगरीय निकायों में लंबित पेंशन, बीमा और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को सुलझाने के लिए 15 अप्रैल को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला शहरी विकास अभिकरण के निर्देशानुसार, ये शिविर सभी निकाय स्तरों पर सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिव्यांग का आशियाना, सचिव पर 10 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप

शिवपुरी, 10 अप्रैल। जिले की कोलारस जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार का मामला गरमा गया है। यहाँ के पंचायत सचिव साहब सिंह रावत पर ग्रामीणों ने आवास की किस्त जारी करने के बदले 10-10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे संवेदनशील मामला एक गरीब दिव्यांग का है, जिसने रिश्वत देने से मना किया तो उसका स्वीकृत आवास ही निरस्त कर दिया गया।

रिश्वत न देने पर सूची से हटाया नाम : पिपरौदा गांव के दिव्यांग देवेंद्र वर्मा ने बताया कि वह झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहा है। तीन महीने पहले उसका नाम आवास योजना की सूची में आया था, लेकिन आरोप है कि सचिव साहब सिंह रावत ने उससे 10 हजार रुपये की मांग की। देवेंद्र ने जब गरीबी का हवाला देकर पैसे देने में असमर्थता जताई, तो सचिव ने पहले प्रक्रिया रोकी और बाद में उसका नाम ही अपात्र बताकर सूची से कटवा दिया।

अपात्रों को मिल रहा लाभ, पात्र भटक रहे : दिव्यांग देवेंद्र का कहना है कि प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन पर उसे यह कहकर जवाब दिया कि उसके पास पहले से पक्का मकान है, जबकि हकीकत में वह झोपड़ी में रह रहा है। वहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में पैसे लेकर उन लोगों के आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं जिनके पास पहले से पक्के मकान, खेती की जमीन और ट्रैक्टर मौजूद हैं। विनोद और मनीष धाकड़ जैसे कई अन्य ग्रामीणों के आवास भी किस्त न मिलने के कारण अधर में लटके हैं।

जांच रिपोर्ट जिला पंचायत भेजी गई : इस मामले में सरपंच प्रतिनिधि बलबीर धाकड़ ने भी सचिव की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए अवैध वसूली की पुष्टि की है। मामला बढ़ने पर कोलारस जनपद सीईओ दिनेश शाक्य ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया था। सीईओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायत कार्यालय भेज दी गई है। जिला पंचायत सीईओ विजय राज के अनुसार, जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी सचिव के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विष्णु मंदिर फीडर से जुड़े क्षेत्रों में आज गुल रहेगी बिजली

शिवपुरी, 10 अप्रैल। शहर के 33/11 के.व्ही. बाणगंगा उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले 11 के.व्ही. विष्णुमंदिर फीडर पर शनिवार, 11 अप्रैल को आवश्यक मेंटीनेंस कार्य किया जाएगा। इस कारण सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक विद्युत प्रवाह पूरी तरह बंद रहेगा। बिजली कटौती से मुख्य रूप से विष्णु मंदिर क्षेत्र, गुलाबशाह दरगाह, सर्वोदय नगर, इंदिरा कॉलोनी, फक्कड़ कॉलोनी और उनके आसपास के इलाके प्रभावित होंगे। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस समयावधि को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यक कार्य पहले ही पूर्ण कर लें।

नि:शुल्क आभूषण निर्माण प्रशिक्षण 16 से

शिवपुरी। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 16 अप्रैल से 14 दिवसीय नि:शुल्क आभूषण निर्माण प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है।

लाड़ली बहनों के खाते में कल आएगी सहायता राशि

शिवपुरी, 10 अप्रैल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अप्रैल (रविवार) को सीहोर जिले के आष्टा से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की अप्रैल माह की किश्त जारी करेंगे। सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की करोड़ों बहनों के खातों में मासिक आर्थिक सहायता राशि अंतरित की जाएगी। शिवपुरी जिले में भी इस कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यापक व्यवस्था की गई है। सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए ताकि वे मुख्यमंत्री के संबोधन और योजना के लाभ से अवगत हो सकें।

सिंधिया के आदेशों की उड़ रही धज्जियाँ

नए कलेक्टर से अवैध रेत खनन पर अंकुश की आस

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 अप्रैल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन-प्रशासन के तमाम दावों और कार्रवाईयों के बावजूद जिले की नदियों का सीना छलनी कर 'पीला सोना' निकालने का खेल धड़ल्ले से जारी है। विशेष रूप से करैरा और आसपास के क्षेत्रों में रेत माफिया इतने बेखौफ हैं कि उन्हें न तो कानून का डर है और न ही प्रशासन का खौफ। स्थिति यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कड़े निर्देशों के बाद भी माफिया उनके आदेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।

करैरा बना अवैध खनन का केंद्र

शिवपुरी जिले के करैरा, दिनारा और नरवर क्षेत्र से बहने वाली नदियों, विशेषकर महुआर और सिंध नदी के घाटों पर माफिया ने अपना जाल बिछा रखा है। रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी बड़ी-बड़ी मशीनों के जरिए रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अवैध उत्खनन के चलते नदियों का स्वरूप बिगड़ रहा है और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँच रही है। नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी रॉयल्टी और अनुमति के सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर रोजाना

सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

सिंधिया के आदेशों की अनदेखी

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दौरों के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि माफिया पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। लेकिन धरातल पर नजारा कुछ और ही है। माफिया के रसूख के आगे सिंधिया के आदेश केवल फाइलों और भाषणों तक सीमित नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रसूखदारों के संरक्षण के कारण ही माफिया के हौसले बुलंद हैं।

खनिज विभाग की 'औपचारिकता' वाली कार्रवाई

ऐसा नहीं है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें समय-समय पर छापेमारी कर ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त करती हैं और जुर्माने भी लगाए जाते हैं। लेकिन यह कार्रवाई महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। कार्रवाई के कुछ घंटों बाद ही खनन फिर से शुरू हो जाता है। जानकारों का कहना है कि जब तक मुख्य माफिया और सिंडिकेट पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक केवल ड्राइवरों को पकड़ने या गाड़ियां जब्त करने से यह कारोबार नहीं थमेगा। कई बार तो विभाग की टीम के पहुँचने से पहले ही माफिया को सूचना मिल जाती है, जो विभाग के भीतर ही मुखबिरों की मौजूदगी की ओर इशारा करती है।

नए कलेक्टर अर्पित वर्मा से जगी उम्मीदें

शिवपुरी के नवनियुक्त कलेक्टर अर्पित वर्मा ने हाल ही में जिले की कमान संभाली है। युवा और ऊर्जावान अधिकारी होने के नाते जिले की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि कलेक्टर वर्मा अवैध रेत खनन के इस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाएंगे।

बढ़ रहा है अपराध और दुर्घटनाओं का ग्राफ

रेत के इस अवैध कारोबार ने न केवल राजस्व को चूना लगाया है, बल्कि जिले में अपराध और सड़क दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा दिया है। तेज रफ्तार रेत से लदे ट्रैक्टरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन हादसे होते हैं। वहीं, माफिया के वर्चस्व की लड़ाई के कारण क्षेत्रों में शांति भंग होने का खतरा भी बना रहता है।

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग नए कलेक्टर के नेतृत्व में माफिया पर किस तरह नकेल कसता है। क्या सिंधिया के 'जीरो टॉलरेंस' के सपने को शिवपुरी में धरातल पर उतारा जा सकेगा या फिर रेत माफिया इसी तरह नियमों की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे।

ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों ने मांग की है कि-

अवैध खनन वाले संवेदनशील घाटों पर सीसीटीवी और चेकपोस्ट लगाए जाएं।

सिंध और महुआर नदी के तटों पर नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।

अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों के मालिकों पर जिला बदर या रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई हो।

अवैध रेत के भंडारण स्थलों (स्टॉक) की जांच कर उन्हें राजसात किया जाए।

कोलारस में बिना ड्राइवर के दौड़ा ट्रैक्टर, जगतपुर तिराहे पर टला बड़ा हादसा

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 अप्रैल। जिले के कोलारस कस्बे के व्यस्त जगतपुर तिराहे पर गुरुवार देर शाम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ सड़क किनारे खड़ा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक स्टार्ट होकर बिना ड्राइवर के ही सड़क पर दौड़ पड़ा। अनियंत्रित ट्रैक्टर को बिना चालक के दौड़ता देख राहगीरों में हड़कंप मच गया, हालांकि एक पेड़ से टकराने के कारण ट्रैक्टर रुक गया और बड़ा हादसा टल गया।

टक्कर लगते ही गियर में होने से हुआ स्टार्ट : जानकारी के अनुसार, कुमरौआ गांव के किसान राजेंद्र धाकड़ अनाज मंडी में फसल बेचकर वापस लौट रहे थे। जगतपुर तिराहे पर उन्होंने अपना ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ा किया और पास ही दुकान पर कुछ सामान लेने चले गए।

इसी दौरान पीछे से आ रहे खोंकर निवासी उत्तम चंदेल के ट्रैक्टर ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। राजेंद्र का ट्रैक्टर गियर में खड़ा था, जिसके कारण पीछे से हुई टक्कर के दबाव से वह अचानक स्टार्ट हो गया और तेजी से आगे बढ़ गया।

पेड़ से टकराकर थमी रफ्तार

चालक न होने के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कुछ दूर तक सड़क पर ही दौड़ता रहा। गनीमत यह रही कि उस समय सामने से कोई अन्य वाहन या राहगीर नहीं आ रहा था, वरना जनहानि हो सकती थी। ट्रैक्टर सड़क से उतरकर किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराया, जिससे उसकी रफ्तार थम गई। इस घटना में ट्रैक्टर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन किसी के हताहत न होने से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी।

विद्या भारती की प्रांतीय योजना बैठक का शुभारंभ

शिवपुरी, 10 अप्रैल। विद्या भारती मध्यभारत प्रांत की चार दिवसीय 'प्रांतीय प्राचार्य/प्रधानाचार्य योजना बैठक-2026' का भव्य शुभारंभ सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय में हुआ। 12 अप्रैल तक चलने वाली इस बैठक में प्रांत के विभिन्न जिलों से आए शिक्षाविद् और पदाधिकारी आगामी शैक्षणिक सत्र की रूपरेखा तैयार करेंगे।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भालचंद्र रावले (क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य), प्रांतीय अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि भालचंद्र रावले ने अपने संबोधन में कहा कि आचार्यों का दायित्व केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर राष्ट्र निर्माण के लिए संस्कारित पीढ़ी तैयार करना है। वहीं, प्रांत प्रमुख डॉ. रामकुमार भावसार ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें गत सत्र की समीक्षा और नए सत्र 2026-27 के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर सामूहिक मंथन किया जाएगा।

ग्यासोबाई के नेतृत्व में बदली तस्वीर, स्वच्छता बनी आदत, कुपोषण पर भी लगा ब्रेक

कई साल की मेहनत रंग लाई : आदिवासी ग्राम आमई बना स्वच्छता का मॉडल

नवभारत न्यूज
पोहरी, 10 अप्रैल। आदिवासी बाहुल्य ग्राम आमई में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जो सकारात्मक बदलाव आज दिखाई दे रहा है, वह रातों-रात नहीं आया, बल्कि एक वर्ष के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। विकास संवाद समिति द्वारा संचालित 'समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन परियोजना' के अंतर्गत ग्रामीणों ने स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है।

ग्राम विकास समूह की सक्रिय वॉलिंटियर ग्यासो बाई के नेतृत्व में पूरे समुदाय ने यह साबित कर दिया कि धैर्य, लगन और निरंतर प्रयास से बड़ा बदलाव संभव है। पिछले 12 महीनों से लगातार चल रहे जागरूकता अभियानों ने ग्रामीणों

की सोच में बड़ा परिवर्तन किया है। शुरुआत में लोगों को समझाना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन ग्यासो बाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने घर-घर जाकर स्वच्छता के महत्व को समझाया और धीरे-धीरे इसे आदत में बदल दिया।

विकास संवाद समिति के अनुसार, कुपोषण मुक्त समाज के लिए साफ-सफाई और स्वस्थ वातावरण बेहद जरूरी है। ग्यासो बाई ने ग्रामीणों को समझाया कि गंदगी से संक्रमण बढ़ता है, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। आज गांव में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी स्वेच्छा से सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं। कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सफाई अब नियमित प्रक्रिया बन चुकी है।

ग्यासो बाई बताती हैं, 'एक साल पहले लोगों का नजरिया अलग था, लेकिन अब स्वच्छता उनकी आदत बन गई है। नियमित बैठकों, रैलियों और आपसी सहयोग से यह बदलाव संभव हुआ है।' विकास संवाद समिति और ग्यासो बाई के प्रयासों से ग्राम आमई आज आसपास के गांवों के लिए स्वच्छता मॉडल बनकर उभरा है। यह पहल न सिर्फ कुपोषण के खिलाफ मजबूत कदम है, बल्कि एक स्वस्थ और जागरूक समाज की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण भी है।

सिकन्दरा में ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारी पर हमला

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 अप्रैल। जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित सिकंदरा परिवहन चेक पोस्ट पर बुधवार की रात जो कुछ भी हुआ, वह न केवल कानून-व्यवस्था की बदहाली को दर्शाता है, बल्कि समाज में महिला सुरक्षा के दावों की कलई भी खोलता है। एक महिला ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जो कानून की रक्षा के लिए तैनात है, यदि अपने ही कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की सुरक्षा का अनुमान लगाना कठिन नहीं है।

पुलिसिया सुस्ती व्यवस्था की विफलता का प्रतीक

यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि समूची प्रशासनिक मशीनरी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। आधी रात का तांडव और वर्दी का अपमान रात के सन्नाटे में बेखौफ बदमाशों का महिला अधिकारी के कमरे में घुसना, गाली-गलौज करना और बेल्टों से उनकी बेरहमी से पिटाई करना यह बताता है कि अपराधियों के मन में वर्दी का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। बदमाशों ने न केवल शारीरिक चोट पहुंचाई, बल्कि नकदी, पीओएस मशीन और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी लूट ले गए। यह एक सुनियोजित दुस्साहस था, जिसमें शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और छेड़छाड़ करना शामिल है। जब रक्षक ही भक्षक के हाथों पिट रहे हों, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए दूरी मात्र दो किलोमीटर पर सक्रियता शून्य इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक परेशान करने वाला पहलू पुलिस की निष्क्रियता है।

जिस चेक पोस्ट पर हमला हुआ, वहां से दिनारा थाने की दूरी मात्र दो किलोमीटर है। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस का समय पर न पहुंचना सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करता है। इससे भी अधिक शर्मनाक यह है कि रातभर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, तब जाकर गुरुवार दोपहर को एफआईआर लिखी गई। पुलिस की यह देरी कहीं न कहीं आरोपियों को संरक्षण देने या मामले को दबाने की कोशिशों का संकेत देती है।

व्यवस्था के सुधार की अनिवार्य आवश्यकता : सिकंदरा चेक पोस्ट की यह घटना चीख-चीखकर कह रही है कि महिला सुरक्षा के नारे केवल कागजों और भाषणों तक सीमित हैं। नामजद आरोपियों की सूची लंबी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में लगने वाला समय पुलिस की कार्यक्षमता का परीक्षण करेगा। यदि एक महिला पुलिस अधिकारी को न्याय पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़े, तो यह व्यवस्था की हार है। प्रशासन को चाहिए कि वह न केवल इन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजे, बल्कि उस विलंब के कारणों की भी जांच करे जिसने अपराधियों के हौसले बुलंद किए। समय आ गया है कि सुरक्षा के दावों से आगे बढ़कर जमीन पर ठोस कार्यवाही की जाए।

'व्यापारियों की मनमानी, मंडी में किसानों के लिए जगह तक नहीं '

मंडी के टीनशेड बने व्यापारियों के गोदाम, किसान धूप में फसल बेचने को मजबूर

नवभारत न्यूज
पोहरी, 10 अप्रैल। कृषि उपज मंडी में किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए टीनशेड अब व्यापारियों की मनमानी की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। जिन टीनशेडों में किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और नीलामी तक इंतजार करने की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वहां अब व्यापारियों ने स्थायी रूप से अपना माल भरकर उन्हें गोदाम बना लिया है।

इस अव्यवस्था का खामियाजा सीधे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दूरदराज गांवों से अपनी मेहनत की फसल लेकर मंडी पहुंचने वाले किसानों को अपनी उपज रखने तक की जगह नहीं मिल रही। मजबूरन उन्हें खुले आसमान के नीचे

फसल रखनी पड़ रही है, जहां बारिश, तेज धूप और धूल से नुकसान का खतरा बना रहता है। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन की लापरवाही और मिलीभगत के चलते व्यापारी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

टीनशेड में कब्जा होने के कारण किसानों के बैठने तक की व्यवस्था खत्म हो गई है और कई किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

कैंटीन के नाम पर खानापूर्ति

मंडी में किसानों के लिए न तो कोई व्यवस्थित कैंटीन है और न ही खाने-पीने की उचित सुविधा। कैंटीन के नाम पर एक ठेले पर सीमित खाद्य सामग्री रखकर औपचारिकता निभाई जा रही है। कूपन व्यवस्था भी सिर्फ कागजों तक सीमित बताई जा रही है, जबकि अंदरखाने इसके दुरुपयोग की चर्चा जोरों पर है।

पानी तक के लिए तरस रहे किसान

भीषण गर्मी के बीच मंडी में शुद्ध और ठंडे पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पानी की टंकियों और आसपास इतनी गंदगी फैली है कि वहां से पानी पीना भी खतरे से खाली नहीं। ऐसे में किसान बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं।

प्रशासन मौन, किसान परेशान

स्थानीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी परिसर में व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए और टीनशेड को किसानों के लिए खाली कराया जाए।

साथ ही कैंटीन, पेयजल और बैठने की मूलभूत सुविधाएं भी तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी, तो यह मंडी किसानों के लिए सहूलियत की जगह परेशानी का केंद्र बनती चली जाएगी।

नन्हे कदमों की आहट और 'लोमड़ी' के डांस के साथ दून जूनियर स्कूल के प्रथम सत्र का आगाज़

शिवपुरी, 10 अप्रैल। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दून जूनियर स्कूल में प्रथम शैक्षणिक सत्र (2026-27) की शुरुआत किसी भव्य उत्सव की तरह हुई। स्कूल के पहले दिन नन्हे सितारों का जिस आत्मीयता और उत्साह के साथ स्वागत किया गया, उसने बच्चों और अभिभावकों दोनों का दिल जीत लिया।

फूलों की वर्षा और कार्टून कैरेक्टर बने आकर्षण : प्रवेश उत्सव को यादगार बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए थे। मुख्य द्वार पर शिक्षकों ने बच्चों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं, परिसर में मौजूद कार्टून कैरेक्टर 'लोमड़ी' बच्चों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहा। अपने मजेदार डांस मूव्स से इस कैरेक्टर ने न केवल बच्चों का मनोरंजन किया, बल्कि पहली बार स्कूल आए बच्चों की झिझक और डर को भी पल भर में दूर कर दिया।

संस्कारमयी और खेल-आधारित शुरुआत : कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ, जिससे बच्चों को शिक्षा और संस्कारों के महत्व से जोड़ा गया। स्कूल की संचालिका सीमा अरोरा ने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को एक खुशहाल वातावरण देना है जहाँ वे अपनी जिज्ञासाओं के साथ बढ़ सकें। स्कूल की इस अनूठी पहल और ममतामयी व्यवहार की अभिभावकों ने भी जमकर सराहना की।